



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २९]

शुक्रवार, जुलै २४, २०१५/श्रावण २, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २४ जुलाई २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XL OF 2015.

A BILL

**FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA OFFICIAL
LANGUAGES ACT, 1964.**

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४०, सन् २०१५।

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ में अधिकतर संशोधन
सन १९६५ करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया
का महा. जाता है :—
५।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभण ।

सन १९६५ का
महा. ५ में नवीन
धारा १क की
निविष्टी।

२. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४, (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की सन् १९६५
धारा १ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात् :— का महा.
५।

मराठी राज्य की
राजभाषा होगी।

“१क. महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा, मराठी होगी।”।

सन १९६५ का
महा. ५ की धारा
२ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २ के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ (ग) “मराठी” का तात्पर्य, देवनागिरी लिपि में मराठी भाषा जिसे समय-समय से जारी किये गये
सरकारी संकल्पों के अधीन जारी करके राज्य में अंगीकृत किया गया है।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ (सन १९६५ का महा. ५) राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिए जिन भाषाओं का उपयोग किया जा सकेगा उन भाषाओं का अंगीकार करने के लिए उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ४ यह उपबंध करती है कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार, **राजपत्र** में, समय-समय से जारी किए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों को छोड़कर, महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद ३४५ में निर्दिष्ट सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए नियत दिनांक से उपयोग की जाने वाली भाषा मराठी होगी।

तथापि, उक्त अधिनियम की धारा १ के पश्चात्, यह उपबंध करने के लिए अलग धारा सुस्पष्ट करना इष्टकर समझा गया है कि, महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा कर्नाटक तथा तामिलनाडू राज्य के राजभाषा अधिनियमों में किए गए समान उपबंधों के तर्ज पर मराठी होगी।

साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा २ का खंड (ग), जो इस राज्य में देवनागिरी लिपि में मराठी भाषा के रूप में, “मराठी” शब्द की परिभाषा सरकारी संकल्प दिनांकित २० जुलाई १९६२ के अधीन अंगीकृत की है, यह प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ताकि समय-समय से जारी किये गये सरकारी संकल्पों के अधीन राज्य में अंगीकृत देवनागिरी लिपि में मराठी भाषा के उपयोग को समर्थ किया जा सके।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ जुलाई २०१५ ।

विनोद तावडे,
मराठी भाषा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई, दिनांकित २४ जुलाई २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।